632वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मार्च 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 632वीं बैठक दिनांक 21/03/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. <u>प्रकरण क्रमांक 8959/2022 बृजनारायण शर्मा, बहेरिया, रूपनगर तसहील ईशगढ़ जिला अशोकनगर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 375, रकबा 1.905 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन–23,636 मी.^{3}, ग्राम लहदपुर तहसील ईशगढ़ जिला अशोकनगर के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् । Env. Consultant - Atmos Sustanable Solutions (P) Ltd., Noida (U.P.).</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 375, रकबा 1.905 हेक्टेयर, ग्राम लहदपुर तहसील ईशगढ़ जिला अशोकनगर म.प्र. पर स्थित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 550वीं दिनांक 16/02/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 21/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री बृजनारायण शर्मा, बहेरिया (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है जिसके पश्चिम दिशा में 20 मीटर पर कच्चा रोड़ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इसके संरक्षण हेतु 30 मीटर का सेट बेक छोडा जायेगा। **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है।** परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान

की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा रोजगार, धूल मिट्टी न उड़े इसके लिये जल छिड़काव की व्यवस्था, वृक्षारोपण, सडक की मरम्मत, आंगनवाडी में कार्य, मेडीकल केम्प इत्यादि बिन्दुओं पर सुझाव/आपत्तियां प्रस्तुत की गई जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर मे समुचित बजट प्रावधान के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे उक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने उपरांत नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान को सम्मिलित कर ली जावेगी। चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 23,636 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.08 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 09.76 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

S. No	Activities	Deliverable	Rate	Total cost (Rs.)
1	Distribution of Public Health Care Center - village Lahadpur Bp kit Suger checkup kit wheel chair, strachar.	5 – Bp kit 5 -Suger Kit 2 - wheel chair 4 - strachar.	Bp kit - 900 /-Rs Suger Kit- 900 /-Rs wheel chair- 6000 /-Rs Strachar- 4000 /-Rs	Bp kit - 4500 Rs Suger Kit- 4500 Rs wheel chair- 12000 Rs Strachar- 16000 Rs
2	Health checkup camp oral and dental	2+2 health camp	Rs 20,000/ camp	80,000
	Total CER budget			**1,00,000**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2290 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

पौधों की प्रजातियां	संख्या	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	टिप्पणी/ सुरक्षा योजना
चिरोल , नीम , जंगल जलेबी , सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	450	बैरियर जोन मे वृक्षारोपण	बार्बेड वायर फेंसिंग से संरक्षण
सीताफल, आवलाँ,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1040	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	-
करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	800	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई 1 मीटर)	फेब्रिकेटेड ट्री गार्ड(5फ़ीट) से संरक्षण
योग	2290		

2. <u>Case No 9183/2022 Shri Jakiuddin Kaji, Owner, Juna Bazar, Tehsil - Alot, Dist. Ratlam, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (20000 Cum per annum) (Khasra No. 172 Govt.), Village - Malya, Tehsil - Alot, Dist. Ratlam (MP) EIA Consultant : Apex Mintech Udaypur (Rj.)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 172), Village - Malya, Tehsil - Alot, Dist. Ratlam (MP) 2.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 575वीं दिनांक 30/05/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 21/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री जकीउद्दीन काजी (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना एवं सुश्री रीना त्रिवेदी (ऑनलाईन) मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा में 140 मीटर पर पक्का रोड़ तथा उत्तर–पश्चिम दिशा में 140 मीटर पर शेड है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान पश्चिमी भाग खुदा हुआ है जहॉ पर गूगल इमेज अनुसार 2013 से खनन् कार्य किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बाताया कि उनको लीज इसी स्थिति में 2021 में आवंटित हुई है, पूर्व निकाले गये खनिज के विवरण माईन प्लान में दर्ज किये गये है, सरफेस मेप पर पिट दिखाया गया है तथा

हमारे द्वारा खनन् नही किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तुतीकरण के दौरान पश्चिम दिशा में 140 मीटर पर पक्का रोड़ के कारण प्रस्तुतीकरण में 60 मीटर का सेट बेक प्रस्तावित किया गया है तथा उत्तर–पश्चिम दिशा में 140 मीटर पर शेड के संबंध में अवगत कराया है, कि यह पास में स्थापित क्रेशर का साईट ऑफिस है । **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है।** परियोजना प्रस्तावक ने जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–19 के सरल क्रमांक–3 पर इस खदान का विवरण दर्ज है । इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव मे वृक्षारोपण, रोजगार, ब्लास्टिंग से ग्रामीणों के स्वास्थ्य को खतरा एंव फसल खराब होने संबंधी बिन्दुओं पर सुझाव/आपत्तियां प्रस्तुत की गई जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर मे समुचित बजट प्रावधान के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट में विंड ब्रेकिग वॉल तथा पक्का रोड़ बनाने का प्रस्ताव दिया गया है किंतु प्रस्तुतीकरण में दिखाए गये ई.एम.पी. में यह प्रस्ताव शामिल नही किया गया है अतः प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है :–

1. ई.आई.ए. रिपोर्ट में दिये गये प्रस्ताव अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. ।
2. समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

3. <u>Case No 9422/2022 Shri Devendar Chowksey S/o Shri Narmada Prasad Chowksey R/o Dvision 08, E-8 Bawadiyakalan, Bhopal (MP)-462023 . Prior Environment Clearance for Proposed Multi-Storey Residential and Commercial Building "Rudraksh Kingston" at Survey No. 112/1, 114/1, 115/1, 115/2, 115/3, 116, 117/4, 117/5, 117/6/2, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 120/1, 120/2, Village Baqwadiyakalan, Tehsil Huzur, Dist. Bhopal (MP). [Total plot size of the project is 97,150 Sq.mtr. (24 acre).] Cat. 8(b) Townships and Area Development projects. Env. Consultant: M/s. Global Mangement & Engineering Consultants International , Jaipur (Raj.)</u>

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Multi-Storey Residential and Commercial Building "Rudraksh Kingston" at Survey No. 112/1, 114/1, 115/1, 115/2, 115/3, 116, 117/4, 117/5, 117/6/2, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 120/1, 120/2, Village Baqwadiyakalan, Tehsil Huzur, Dist. Bhopal (MP). The total plot size of the project is 97,150 Sq.mtr. (24 acre). The proposed project consists of Hotels, Duplex, Flats, Multi-story building, Commercial Shops, Club house and Hotel.

The ToR was recommended in 609th SEAC meeting dated 07.12.22. PP has submitted EIA report and thus the case was scheduled in agenda.

The case was presented by PP Shri Devendra Chocksay, Mr. Vikas Shukla, Architect and their Environmental Consultant Ms. Tushali Jagwani from M/s. Vibrant Techno Labs. Pvt. Ltd., Jaipur. During presentation PP submitted that previously they have submitted project proposal through M/s Global management & Engineering Consultant International, Jaipur but their validity of accreditation was thus to avoid further delay in appraisal, they have now hired M/s M/s. Amaltas Enviro Industrial Consultant LLP, Gurugram as project consultant for EC. During presentation, PP submitted that they again have recently changed their consultant and now M/s. Vibrant Techno Labs. Pvt. Ltd., Jaipur is their consultant for which they have intimated through mail (to SEIAA & SEAC on dated 18/03/23) with an affidavit dated 18/03/23 for change of consultant. Fllowing details were submitted by the consultant:

- The proposed project **"Rudraksh Kingston" Proposed Multi-Storey Residential and Commercial Project** by Shri. Devendra Chouksey S/o Shri. N.P. Chouksey which is to be developed at Village – Bawadiya kalan, Tehsil – Huzur, District – Bhopal, & State – Madhya Pradesh.
- The total plot size for the project is **97,150 m^2 (24 acre**). The project will be developed for Commercial and residential purpose.
- Flats + Duplex + EWS + LIG + Commercial Shop + Hotel + School, Basements: Parking & Services
- The **Total Built up Area** for Residential and Commercial **2,94,024 m^2**, which is greater than 1,50,000.00 m^2 therefore, the project comes under **schedule 8(b); category B** as per the EIA Notification 14th September, 2006.
- The Co-ordinates of the project site are latitude from 23°10'43.56"N to 3°10'43.50"N and longitude from 77°26'48.21"E to 7°26'48.14"E. The project is covered in toposheet no. – F43F7, Survey of India (SOI).
- Field studies has been referenced nearby project study which is almost attached to the project site for the period 1st March 2022 to 31st May 2022 (Pre - Monsoon) to determine the existing conditions of various environmental attributes.

S. No.	Particulars	Area (m^2)
1	Total Land	97150 (24.00 Acres)
2	Area Under 60 M Road	12847.65 Sqm
3	Area Under 24M Road	2904.61 Sqm
4	Planning Area including future development	81,397.74
5	Ground Coverage Area (30 %)	24,419.32
6	Total Built Up Area (FAR)	1,69,658.00
7	Total Built Up Area (Non FAR)	1,24,366.00

8	Total Built Up Area (FAR + Non FAR)	2,94,024.00
9	Green Area	8,139.77
10	Hotel (2)	75 Rooms each
11	Club House	5574.18
12	No. of EWS & LIG	EWS - 30 units, LIG - 20 Units
13	No. of Commercial Shops	500.00
14	Basement Area	64591.96
15	Parking Details (Basement, Stilt, Open)	2 Levels of Basement Parking Only
16	Total No. of Units (Flats)	486.00
17	Total No. of Units (Duplex)	52.00
18	Road MOS	Front 15, Sides 7.5

Items	**Salient Features of the project**
Name of Project	"Rudraksh Kingston" Proposed Multi-Storey Residential and Commercial Building
Name of the Project Proponent	Shri. Devendra Chouksey S/o Shri. N.P. Chouksey
Location	Village – Bawadiyakalan, Tehsil – Huzur, District – Bhopal, & State – Madhya Pradesh.
Nearest Railway Station	Misrod Railway Station is about 1.67 km in SE Direction
Nearest Airport	Bhopal Airport: 16.32 in NW Direction
Nearest Highway	NH – 46 : 6.67km in East Direction
Size of plot	97,150 Sqm. (24 Acre)
Total Built Up Area	2,94,024.00 sqm
Building Height	45 M (As Mentioned in T&CP Letter Point No. 05)
Estimated Population	11,043
Total Water Requirement	1028.505 KLD
Fresh Water Requirement	633.505 KLD
Flushing Water	395 KLD
Power Requirement	Approx 5091.524 KW
STP Capacity	900 KLD
D.G. Sets	There is provision of 6 no. of DG set of total capacity 2125 kVA (3*500=1500 kVA + 250 kVA + 250 kVA +125 kVA) for power back up in the Project.
Solid Waste Generated	1808.23 Kg/day
Project Cost	227.06 rores

During presentation it was observed by the committee that there are several mistakes in the EIA report which are grave in nature and needs clarification from PP/Consultant and revision in EIA report such as, In Chaptor-I of EIA at page no. 5 it is mentioned under heading ***"Consent to Establish & Consent to Operate"- The unit had already obtained CTE & CTO before start of construction. As the project is a violation case and project has been prosecuted. Therefore, CTE/CTO are null & void and project proponent will obtain a fresh after obtaining Environment Clearance (EC)",*** while at the time of ToR neither this fact was not mentioned not was evident from the Google image. PP was also flabbergasted knowing above statement mentioned in the EIA report and immediately submitted that it's not a case of violation and the contants mentioned in the EIA report are falls and misleading. Thus committee asked PP and their newly appointed consultant M/s. Vibrant Techno Labs. Pvt. Ltd., Jaipur to review the entire EIA and revise the same as per given ToR and site conditions for further consideration of this case.

4. <u>Case No. - 9241/2022 M/s J.P.Minerals Industries, Smt. Renu Banshal, Prop., E-8, 9, 10, Industrial Area, Jaderua, Dist. Morena, MP – 476001. Environment Clearance for Cement Grinding Unit , Capacity- 300TPD (Ball Mill 3X100 TPD) at E-8, 9, 10, Industrial Area, Jaderua, Tehsil Joura , Dist. Morena, (MP) . Category: 3(b) Cement Project. Env. Con. – M/s. RSP Green Development & Laboratories Pvt. Ltd. Shibpur, Howrah (W.B.).</u>

This is a case of Cement Grinding Unit Capacity- 300TPD (Ball Mill 3X100 TPD). The project is covered as item 3(b) in the schedule of EIA notification as standalone grinding unit and hence requires EC from SEIAA before commencement of any activity at site. The application was on-line forwarded by SEIAA to SEAC for scoping so as to determine TOR to carry out EIA and prepare EMP for the project.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 581वीं दिनांक 24/05/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण आज सेक की 632वीं बैठक दिनांक 21/03/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

5. <u>Case No. – 7789/2020 Shri Arun Singh Yadav S/o Late Shri Santosh Singh Yadav, Village - Rajgarh, Tehsil - Bijoli, Dist. Jhansi, UP – 284135 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.037 ha. (44923 cum per annum) (Khasra No. 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18), Village - Baganvar, Tehsil - Orcha, Dist. Niwari, (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18), Village - Baganvar, Tehsil - Orcha, Dist. Niwari, (MP) 3.037 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 463वीं दिनांक 01/10/2020 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 21/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अरूण सिंह यादव, (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सिया के पत्र क्रमांक 240 दिनांक 20/12/22 के द्वारा यह खदान संतोष सिंह यादव के स्थान श्री अरूण सिंह यादव के नाम पर स्थानांतरित हो गई तथा अनुमोदित खनन् योजना 31/03/23 तक वैध है जिसके नवकरण हेतु आवेदन कर दिया गया है । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खनन् क्षेत्र निजी भूमि पर आवंटित है जिसका मध्य मे खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पुराना पिट है जिसे अनुमोदित खनन् योजना के सरफेस मेप पर दिखाया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि पूर्व दिशा में 180 मीटर की दूरी पर पक्का रोड़ तथा 130 मीटर की दूरी पर आबादी है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आबादी वाले क्षेत्र से 70 मीटर का सेट बेक (0.36 हे.) प्रस्तुतीकरण में नॉन माईनिंग जोन के रूप में प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि दक्षिण–पश्चिम दिशा में 66 मीटर एवं 180 मीटर की दूरी पर शेड है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह मुर्गी पालन केंद्र के शेड है । इसी प्रकार प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि दक्षिण दिशा में 175 मीटर की दूरी पर आबादी है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आबादी वाले क्षेत्र से 25 मीटर का सेट बेक (0.21 हे.) प्रस्तुतीकरण में नॉन माईनिंग जोन के रूप में प्रस्तावित किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–26 के सरल क्रमांक–49 पर इस खदान का विवरण दर्ज है किंतु आक्षांश–देशंशा दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव मे वृक्षारोपण किया जाये **एवं** आंगनवाडी के लिये कुछ कार्य किये जाये संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिन्हे उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई.आर. मे समुचित बजट के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार

सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा । **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है।** परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 44,923 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.14 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 05.32 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित **गतिविधियां**	
जन सुनवाई आधारित सीईआर गतिविधियां	राशि रू.
ग्राम पंचायत के माध्यम से ऑगनवाड़ी केन्द्र वनगावंहार में बच्चों के लिये खिलौने एवं झूले का सहयोग किया जायेगा।	50,000
ग्राम के विकास कार्य के लिए ग्राम पंचायत को 20,000/– राशि का सहयोग किया जायेगा।	20,000
योग	70,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3700 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	**बैरियर जोन**	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरौल, सीताफल, बेल, इमली, आंवला, कटहलए आम, अमरूद, जामुन और उपलब्ध देशी प्रजातियॉं।	1000
2	**परिवहन मार्ग** (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	नीम, आमए पीपल, सेमल, पुत्ररंजीवा, मौलश्री, इत्यादि।	200
3	वनगावंहार के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में	कदम्ब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवाए मोलश्री, गुलमोहर इत्यादि।	20
4	गॉंव वनगावंहार के ग्रामवासीयों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, रूद्राक्षए सीता अशोक, मुनगा इत्यादि।	2480
		योग	3700

6. **Case No. – 6417/2019 Smt. Pratima Raje Rana W/o Shri Sher Singh Rana R/o 119/1 B.T. Ganj, Rajputana, East Roorki] Haridwar (Uttarakhand). (Old PP 6417/2019 Shri Rana Pratap Singh, R/o Suryanchal Garhi, VPO Ghuwara, Dist. Chhatarpur, MP. Prior Environment Clearance for Dolomite Quarry in an area of 18.21 ha. (77,010 TPA) (Khasra No. 1008), Village - Tigoda, Tehsil - Banda, Dist. Sagar (MP).**

This is case of Dolomite Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 1008), Village - Tigoda, Tehsil - Banda, Dist. Sagar (MP) 18.21 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 389वीं दिनांक 09/08/2019 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण आज सेक की 632वीं बैठक दिनांक 21/03/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

7. **प्रकरण क्रमांक 9023/2022 – श्रीमती मंजू सिंह, पुष्पराज कॉलोनी, आंध्रा बैक के सामने, गली न. 1, पोस्ट एवं जिला सतना (म.प्र.) लाईम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन माईन, खसरा नं. पी303, पी309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, पी317, पी319, पी320, 399, 432, 433, 434, 435, 436 444, 445, 446, 447, 448, 451, 452, 457, 458 एवं 459 रकबा 06.794 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन–3,00,000 टीपीए, ग्राम बरहीया, तहसील – मैहर जिला – सतना (म.प्र) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आनलाईन प्राप्त यह प्रकरण लाईम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. पी303, पी309,310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, पी317, पी319, पी320, 432, 433, 434, 435, 436 444, 445, 446, 447, 44/8, 451, 452, 457, 458 एवं 459 रकबा 6.794 हेक्टेयर, ग्राम बरहीया, तहसील मैहर जिला सतना (म.प्र) पर स्थित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 556वीं दिनांक 02/03/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण आज सेक की 632वीं बैठक दिनांक 21/03/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

8. <u>Case No 9720/2023 Shri Durgaprasad Nagar S/o Shri Panna Lal Nagar, R/o Village-Bhatkhedi, Tehsil-Sarangpur, District-Rajgarh (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Bhatkhedi Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (5000 Cum per annum) (Khasra No. 950/1), Village- Bhatkhedi, Tehsil-Sarangpur, District-Rajgarh (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 950/1), Village- Bhatkhedi, Tehsil-Sarangpur, District-Rajgarh (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री दुर्गा प्रसाद नागर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराधव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजराज) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 69 दिनांक 30/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 4.0 हे. है। अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है जिसके उत्तर पूर्वी दिशा एंव दक्षिण दिशा मे 327 एंव 100 मी. पर जल–भराव क्षेत्र है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तुतीकरण के दौरान अवगत कराया है, कि इनके संरक्षण हेतु गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक प्रस्तावित किये गये है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र मे कुल 05 पेड़ लगे है जिनमें से 02 पेड काटे जायेगे तथा उनके एवज् 20 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेगे । परियोजना प्रस्तावक ने यह भी अवगत कराया कि अनुमोदित खनन् योजना अनुसार इस प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है तथा खनन् कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि आवंटित क्षेत्र के कुछ भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक बताया कि यह क्षेत्र हमें इसी स्थिति में 09/2022 में आवंटित हुआ है तथा पिट हमने सरफेस मेप पर दिखाया है एवं हमारे द्वारा खनन् कार्य

नही किया गया है । **प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है।** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ (म.प्र.) के पत्र क्र0. 60 दिनांक 30/01/2023 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे जोड ली जावेगी। चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 5,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.57 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 02.46 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर.	राशि (रू.में)
शासकीय प्राथमिक शाला में 1 प्रिंटर एवं एक टेबल उपलब्ध करवाया जावेगा ।	30,000
ग्राम में स्थित प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में 2 स्ट्रेचर 2 व्हील चेयर एवं पदस्थ चिकित्सक के परामर्श में जरूरत के हिसाब से उपयोग हेतु सामग्री प्रदान की जावेगा।	30,000
योग	60,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2500 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1	बैरियर जोन	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– खमेर, पीपल, सिस्सू, बबूल, महुआ, जंगल जलेबी, नीम, सीताफल, चिरोल आदि।	430
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– जंगल जलेबी, नीम, सिस्सू, पीपल, चिरोल, करंज, सफेद कस्टॉर आदि।	300

3	दूसरे वर्ष में ग्राम के नजदीक स्थित गौशाला परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः— कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, आम, मुनगा, करंज, आदि।	100
4	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः— आमला, आम, संतरा, सीताफल कटहल, मुनगा, जामफल आदि।	1670
		योग	2500

9. <u>Case No 9739/2023 Shri Hukum Singh Lodhi, Owner, R/o Jammbar, Post-Imaliya, District-Vidisha (MP) Prior Environment Clearance for Tori Murrum Quarry in an area of 2.00 ha. (7002 Cum per annum) (Khasra No. 186/1 Govt.), Village-Tori, Tehsil-Vidisha, District-Vidisha (MP)</u>

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 186/1 Govt.), Village-Tori, Tehsil-Vidisha, District-Vidisha (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हुकुम सिंह लोधी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स अमलतास इंवारो इंडस्ट्रीयल कंसलटेंटस एल.एल.पी. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 375 दिनांक 06/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है तथा पहाड़ी पर स्थित है जिसकी सतह से ऊंचाई लगभग 26 मी. है। खदान क्षेत्र के पश्चिमी सीमा से 249 मी. पर हलाली नदी, पहाड़ी की दूसरी ओर पूर्वी दिशा मे दूसरी ओर 250 मी. की दूरी पर आबादी है एवं कच्चा रोड पश्चिम दिशा मे 81 मी. की दूरी पर स्थित है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तुतीकरण के दौरान अवगत कराया है, कि नदी के संरक्षण हेतु गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक भी प्रस्तावित किये गये है तथा प्रकरण मुरूम का होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि आवंटित क्षेत्र के मध्य भाग में रूट–स्टॉक विकसित है अतः इस भाग को संरक्षित किया जाये तथा इस भाग कंटूर ट्रेंच बना कर उसमें सीड–सोइंग की जाये । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 373 दिनांक 06/02/2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि खनन पट्टे के ब्यौरे को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा।. चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक

04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम – 7,002 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.38 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 02.01 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर.	राशि (रू.में)
ग्राम टोरी के आँगनवाड़ी केंद्र में दरी एवं झूले व अन्य जरूरत के अनुसार सामग्री का वितरण	40,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1	बैरियर जोन	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	150
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	350
3	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
4	ग्रामवासियो में वितरण हेतु) ग्राम पंचायत जम्बार)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
5	ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत जम्बार के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
6	ग्राम पंचायत जम्बार के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
		योग	2000

10. <u>Case No 9743/2023 Shri Neeaj Mangal, Owner, R/o Lehroni, Tehsil-Karahal, District-Sheopur (MP) Prior Environment Clearance for Karathal Stone Quarry in an area of</u>

2.00 ha. (5088 Cum per annum) (Khasra No. 1412/1/1 Govt.), Village- Karathal, Tehsil-Karahal, District-Sheopur (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1412/1/1 Govt.), Village- Karathal, Tehsil-Karahal, District-Sheopur (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री नीरज मंगल (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 866 दिनांक 31/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोर्द खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है। अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रकरण के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से समिति ने पाया कि पी–2 फार्म अनुसार आवंटित खसरा लगभग 23.0 हे. का है जिसमें आई.टी.आई. हेतु भवन निर्माण, खेल के मैदान का निर्माण, ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण तथा सांख्यिकी भवन निर्माण इत्यादि कार्य किये जाना प्रस्तावित किये गये है जो संवेदनशील प्रकृति के है तथा इन्ही के पास पत्थर की एक खदान स्वीकृत की गई है जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है । अतः समिति की अनुशंसा है कि संबंधित कलेक्टर उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में पुर्नविचार कर इस स्थल पर खदान् स्वीकृति के संबंध में अपने मत से समिति को अवगत कराये तथा यह भी स्पष्ट करे कि प्रस्तावित आई.टी.आई. भवन, खेल का मैदान, ट्रेनिंग सेंटर तथा सांख्यिकी भवन की दूरी आवंटित खदान् से कितनी है। संभवतः यह क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के दायरे में आता है अतः समिति की अनुशंसा है कि संबंधित कलेक्टर यह सुनिश्चित करले कि यह क्षेत्र पेसा एक्ट, 1996 में अधिसूचित क्षेत्र या नही एवं यदि यह क्षेत्र पेसा एक्ट 1996 में अधिसूचित है तो क्या उसमें निहित प्रावधानो के अनुरूप यह स्वीकृति प्रदान की गई है ।

11. Case No 9759/2023 Shri Aabhash Gupta, Proprietor, M/s Ananya Engineering Private Limited, R/o Rudraksh Park Phase-II, Flat No. 402, Bawadiya Kalan, District-Bhopal (MP)-462042, Prior Environment Clearance for Badayala Chourasi Stone Quarry in an area of 3.90 ha. (60000 Cum per annum) (Khasra No. 2/1 Govt.), Village-Badayala Chourasi, Tehsil-Piploda, District-Ratlam (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 2/1 Govt.), Village-Badayala Chourasi, Tehsil-Piploda, District-Ratlam (MP) 3.90 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अभिलाष गुप्ता के अधिकृत प्रतिनिधी श्री राजकुमार राजपूत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराधव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी. , वडोदरा (गुजराज) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 442 दिनांक 23/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार लीज एरिया खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि संभवतः यहां पूर्व में कोई खदान् कार्यतरत रही है जिसकी यह पिट है । हमको खदान् इसी स्थिति में दिनांक 25/01/23 को आवंटित हुई है तथा पिट को हमने अनुमोदित खनन् योजना के सरफेस मेप पर दिखाया है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के चारो ओर विंड मिल स्थापित है (पूर्व दिशा मे 120 मी., दक्षिण–पूर्व दिशा में एंव 190 पर 313 मी., दक्षिण–पश्चिम दिशा में 210 मी., उत्तरी–पूर्व दिशा मे 195 मी. की दूरी पर तथा दक्षिण–पश्चिम दिशा मे 200 मी. पर स्थित है) अतः चारो ओर विंड मिलों की स्थापना के कारण पर्यावरण की दृष्टि से स्थल संवेदनशील है क्याकि खनन् के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल के कण विंड मिल के द्वारा निर्मित किये गये विंड वेलोसिटी के कारण बहुत दूर तक जाने की संभवना रहेगे। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है तथा खनन् रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जायेगा तथा जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, उज्जैन ने पत्र क्रमांक 344 दिनांक 16/03/23 के माध्यम से अपनी अनापत्ति दी है । समिति ने जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, उज्जैन ने पत्र क्रमांक 344 दिनांक 16/03/23 के पत्र का अवलोकन किया तथा पाया कि जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, उज्जैन ने मेसर्स सुजलान ग्लोवल सर्विसिस द्वारा जारी पत्र को अग्रेषित किया है तथा अपना कोई मत उस पर अंकित नही किया है जो उपरोक्त परिस्थिती में आवश्यक है अतः समिति की अनुशंसा है कि गूगल इमेज अक्टूबर 2022 के अनुसार चूंकि प्रस्तावित खदान के आस–पास एक–दो नही बल्कि कई विंड मिल (05 से 06) स्थापित है तथा ओर प्रस्तावित हो सकती है अतः संबंधित जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी उपरोक्त परिस्थितयों के परिप्रेक्ष्य में समग्र रूप से विचार कर अपनी अनुशंसा से समिति को अवगत कराये ।

12. <u>Case No 9758/2023 Shri Rajendra Singh, R/o Village-Rupeta, Tehsil-Ashta, District-Sehore (MP), Prior Environment Clearance for Rupeta Crusher Stone Mine in an area of 1.00 ha. (8600 Cum per annum) (Khasra No. 167/1/24 Govt.), Village- Rupeta, Tehsil-Ashta, District- Sehore (MP)</u>

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 167/1/24 Govt.), Village- Rupeta, Tehsil-Ashta, District- Sehore (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

632वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मार्च 2023

आज दिनांक 21/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 423 दिनांक 31/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार लीज एरिया खुदा है जो कि वर्ष 2019 के बाद खुदी हुई है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि हमे इसी स्थिति में खदान वर्ष 2020 स्वीकृत हुई है। गूगल इमेज अनुसार दक्षिण एंव दक्षिण–पूर्व दिशा मे कंटुर ट्रेंचेस खदान से लगी हुयी है। उत्तर दिशा मे 183 मी. की दूरी पर हाईवे है। दक्षिण–पूर्व दिशा में 383 मी. पर प्राकृतिक नाला है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तुतीकरण के दौरान अवगत कराया है कि नाले के संरक्षण हेतु गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक भी प्रस्तावित किये गये है। उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क्र0. 53 एंव सरल क्र0. 46 पर दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 8600 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.49 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 05.15 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर.	राशि (रू.में)
ग्राम पंचायत रूपेटा के शासकीय स्कूल में 15 टेबल एवं 15 कुर्सी की व्यवस्था की जावेगी ।	**60,000/–**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1	बैरियर जोन	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	350
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	150
3	रूपेटा ग्रामवासियों में वितरण हेत	बेल, इमली, आंवला, कटहल, मुनंगा, आम, रुद्राक्ष, सीताअशोक,	680

		अमरूद, इत्यादि ।	
4	शासकीय विद्यायल रूपेटा में	कदंब, अमलतास, मोलश्री, अशोक, नीम, गुलमोहर इत्यादि।	20
		योग	1200

13. <u>Case No 9658/2023 Shri Himanshu Meena, Partner, R/o 9 A, Paramount Villa, Ansals, Shyamla Hills, District-Bhopal (MP)-462013 Prior Environment Clearance for Kadari Sand Quarry in an area of 1.50 ha. (12000 Cum per annum) (Khasra No. 672), Village-Kadari, Tehsil-Chhatarpur, District-Chhatarpur (MP)</u>

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 672), Village-Kadari, Tehsil-Chhatarpur, District-Chhatarpur (MP) 1.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की पूर्व 621वीं बैठक दिनांक 20/02/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री हिमांशु मीणा (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया। गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1868 दिनांक 02/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. कम है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान बुरहा नाला में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि छतरपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–78 के सरल क्रमांक–48 पर इस खदान का विवरण दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–27,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 12,000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था । अतः पर्यावरणीय अभिस्वीकृति इसी मात्रा अर्थात 12,000 घनमीटर/वर्ष हेतु अनुशंसित किया जाये । ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान बुरहा नाला के पूरे भाग में स्वीकृत की गई है, जिसका लगभग 75 प्रतिशत भाग जल में डूबा हुआ है तथा आवंटित खनन् क्षेत्र मे एक चेकडेम भी बना है, अतः इसके दोनो ओर सेफजोन – नॉन माईनिंग के रूप में छोड़ा जाना चाहिए तथा परियोजना प्रस्तावक उचित सरंक्षण योजना पुनरीक्षित सरफेस मेप के साथ प्रस्तुत करें। समिति की यह भी अनुशंसा है कि संबंधित खनिज अधिकारी से यह जानकारी भी प्राप्त की जाये कि चेकडेम के कारण आवंटित खनन् क्षेत्र में यदि पानी भरा है तो खनन् किस प्रकार संभव होगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल दिनांक 06/03/2023 अपलोड कर दी गई है, अतः प्रकरण को समिति के समक्ष दिनांक 21/03/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना

प्रस्तावक श्री हिमांशु मीणा (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ,. उ.प्र. उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 451 दिनांक 03/03/2023 में खनिज अधिकारी ने सूचित किया है कि उक्त स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र में अप्रेल माह से मई माह तक जल–भराव कम हो जाता है जिससे खदान मे उत्खनन कार्य किया जा सकता है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत खनन् क्षेत्र 1.50 हे. में से 0.87 हे. क्षेत्र चेक डेम के कारण नॉन माईनिंग जोन (चेक डेम के दोनों ओर 250–250 मीटर) छोड़ा गया हैं तथा खनन् 0.63 हे. में 02 मीटर की गहराई तक अप्रैल माह के पश्चात् किया जायेगा, जिसे प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न सरफेस मेप मे दिखाया गया है । स्वीकृत लीज की समयावधि एक वर्ष से भी कम (जून, 2023 तक) ही है । समिति की यह चिंता है कि इतनी कम अवधि होने के कारण इस प्रोजेक्ट के तहत् रोपे गये पौधों की देख–भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ–साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा करेंगा, जिससे विभाग वृक्षोरोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 12,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.20 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 02.15 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रूपये 06.90 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे भू–प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वंयम वृक्षो की प्रजातियॉ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।
5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य

ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगेः–

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 02 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख–रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर	करंज, कट्ग बॉसं जामुन कहवा खस, नागर मोथा , पुत्रंजीवा, मौलश्री खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	**1000**
2	आावंटित लीज क्षेत्र के आसपास उपलब्ध क्षेत्र (केंचमेंट एरिया–इच्छुक ग्रामीणों के खेत) मे	कट्ग बॉसं, कहवा, खमेर, सफेद, सिरस, नीम, सेमल, आंबला, हरसिंगार, कालासिरस,एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ वन विभाग के सुझाव अनुसार	600
3	ग्राम कदारी के ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाडी, शासकीय विद्यालय में	कदंब, कचनार, अमलतास, अशोक, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	200
		योग	1800

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून, 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि(रु. में)**
ग्राम कदारी के शासकीय हाई स्कूल में एक कम्प्युटर, प्रिंटर, प्रिंटर, टेबल के साथ	60,0000/–

14. <u>Case No 9715/2023 Shri Jeevan Patel, Partner, M/s Shree Krishna Enterprises, R/o 30, Shree Mangal State Near Shubh Labh Valley, Bengali Square, District-Indore (MP)-452001, Prior Environment Clearance for Kampel Stone M-Sand & Murrum Quarry in an area of 3.44 ha. (Stone-17236, Murrum-11725 & M-Sand-17236 Cum per annum) (Khasra No. 2471, 2574, 2573/4, 2573/1, 2573/ Pvt.), Village-Kampel, Tehsil-Khudel, District-Indore (MP)</u>

This is case of Stone M-Sand & Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 2471, 2574, 2573/4, 2573/1, 2573/3 Private), Village-Kampel, Tehsil-Khudel, District-Indore (MP) 3.44 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री जीवन पटेल (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराधव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजराज) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1736 दिनांक 12/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 14.258 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के अंदर दक्षिण दिशा मे कुछ अर्धनिर्मित संरचना दिखाई दे रही जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिना पर्यावरणीय अभिस्वीकृति कार्य शुरू कर दिया गया है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक व उनके पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस खदान के पश्चिम दिशा में स्थित एक अन्य खदान का कुछ समान इस खदान् को आवंटित क्षेत्र में रखा है । समिति ने पाया कि जो अर्धनिर्मित संरचनाये दिख रही है वह संभवतः अर्थ वर्क के उपरांत फाऊंडेशन का कार्य किया जा रहा है जो एम.सेंड प्लॉट के निर्माण से संबंधित हो सकता है तथा यह प्रकरण वायलेशन की श्रेणी में आयेगा। अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक संर्पूण आवंटित खनन् क्षेत्र की ड्रोन व्हीडिओ ग्राफी कराकर एक मिनिट का व्हीडिओ तथा कम से कम पांच जी.पी.एस. टेग्ड फोटोग्राफ इन अर्धनिर्मित संरचनाओं के प्रस्तुत करे ताकि प्रकरण में निर्णय लिया जा सकें ।

15. <u>Case No 9744/2023 Shri Babulal Mandloi, Executive Engineer, Narmada Valley Development Authority, Division-21, Sanawad, Khargone (MP) -451111. Prior Prior Environment Clearance for Jhirniya Micro Lift Irrigation Project in an area of 39,520 ha.(CCA), Gross command area (GCA- 53969 Hectare, at 86 villages of Jhirniya Tehsil of Khandwa and Pandhana Tehsil of Khargone (MP) . Category-1-c, [under River Valley and Hydroelectric Projects].</u>

This is a River Valley projects involving > 10,000 ha. of culturable command area falls under category "B" and have been mentioned at SN. 1(c) column B of Schedule of EIA Notification, hence such projects are required to obtain prior EC from the SEIAA.

This is case of Prior Environment Clearance for Jhirniya Micro Lift Irrigation Project in an area of 39,520 ha.(CCA) at 86 villages of Jhirniya Tehsil of Khandwa and Pandhana Tehsil of Khargone (MP). This is one of the three dams proposed as part of Chhindwara Irrigation Complex Scheme.

The case was presented by the Dr. Sandeep Jadhav, Env. Consultant from M/s. MITCON, Pune along with PP Shri Babulal Mandloi, Executive Engineer, Narmada Valley Development Authority, wherein PP stated the main objective of JHIRNIYA MICRO LIFT IRRIGATION SCHEME is to provide irrigation facilities to the water-scare areas in upper

reaches of JHIRNIYA, tehsil of Khargone district & Khandawa, Pandhana Tehsil of Khandwa Dist. where the level of irrigation is very much less as compare to national irrigation percentage. The Jhirniya Micro Lift Irrigation Scheme has been conceived to catter irrigation water to about 39520 Ha CCA in Jhirniya, Khandwa & Pandhana tehsil of Khargone & Khandwa districts 86 villages will be benefited by this scheme. Jhirniya MLIS take's off a discharge of 14.83 Cumecs from ISP main canal at RD 39.80 Km. near village Daudwa in Distt. Khargone.

Salient Features and Information of Components

Name of the Project	**Jhirniya Micro Lift Irrigation Scheme**
Type of the Project	Irrigation
Supply Source/Lifting Point	ISP main canal near village Daudwa (PS1)
Latitude/Longitude	$76^0$08'37"E / $22^0$02'55."N
District	Khandwa & Khargone
Total number of village to be benefited	**86 nos.**
Delivery Point	Near village 1. Bhatalpura (PS2) 2. Bhilankhera (PS3 & DC1) 3. Kusumbia (PS4 & DC2) 4. Pitchoriya (DC3)
Length of Main Canal (in m) (for Irrigation project);	60000 (60kms)
Length of Distributaries (in m) (for Irrigation project) :	1500000 (1500kms)
Cultural Command Area (ha) :	39520

Command Area Details

District	Taluka	Villages Benefited	Projected GCA in Ha	Created CCA in ha.
Khargone	Jhirnia	49	27695	19694
East Nimar (Khandwa)	Khandwa	06	6691	5629
	Pandhana	31	19583	14197

	Total	**86**	**53969**	39520

Land Requirement

Nature of Land	**Requirement in (Ha)**
Non-Forest Land	**0**
Forest Land	**17**
Total	**17**

Location of Scheme :

The Scheme area lies in Khargone and Khandwa District of MP. The supply source i.e. ISP Reservoir, lifting point of pump houses and rising main lie in Khargone distt. of Nimar region and water lifted from ISP main canal at RD 39.80 Km. Near Daudwa village in Khargone distt. And command area lies in 86 Villages Jhirniya, Khandwa & Pandhana tehsil of Khargone & Khandwa districts.

Regarding Land Acquisition & Resettlement of Oustees, PP stated that the proposed scheme is not a storage scheme hence no land will be submerged. The canal system is proposed through underground pipes, (minimum 1m. below ground level), thus no land will be permanently acquired for pipe line system only temporary land acquisition will be acquired under pipe line duct act. Only land for pump houses, rising man, approach road to pump houses (if found necessary) and for building construction at pump house will be acquired. No Abadi area is proposed to be acquired. Since no balancing reservoir is proposed in the scheme and no land will come under submergence therefore environmental clearance will be given by Govt. State level. Committee after deliberations recommended to issue standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's:-

1. Since project involves 17.0 ha., forest area, F.C. clearance has to be obtained by PP and copy of the same should be submitted with EIA report.
2. Bifurcation of RF and PF details (if any).
3. Status of land as per land recored register of concerned collector.
4. CAT plan shall be prepared and the same shall be approved by the concerned DFO.

5. KML of FC clearance and EC clearance shall be submittd with EIA report with forest compartment history as per current forest plan.
6. Thematic disgram showing channel from water lifting point to the distribution area shall be submitted with EIA report.
7. Details of actual area occupied by pipes and other other area (such as for movement of trucks and logistic support) shall be calculated and discussd in the EIA report.
8. It shall also be verified if any area is falling under PESA Act, 1996, if yes their provisions shall accordingly be complied.
9. Narmada Development Division has applied for distance from nearby National Park/ WLS vide letter no. 326 dated 31.01.23 and the same shall be submitted with EIA report.
10. Narmada Development Division has applied for interstate distance of the project vides letter no. 328 dated 31.01.23 and the same shall be submitted with EIA report.
11. Tectonics, seismicity and history of past earthquakes in the area. A site specific study of the earthquake parameters will be done. The results of the site specific earthquake design shall be sent for approval of the NCSDP (National committee of Seismic Design Parameters, Central water commission, New Delhi for large dams.
12. If any issue involved to R&R, shall be elaborated in EIA with proper provisions issued by various State /central Government orders/ notification. In case of R&R is proposed then list of all the Project Affected Families (PAFs) with their name, age, educational qualification, family size, sex, religion, caste, sources of income, land & house holdings, other properties, occupation, source of income, house/land to be acquired for the project and house/land left with the family, any other property, possession of cattle, type of house etc.
13. Resettlement and Rehabilitation Plan needed to be prepared on the basis of findings of the socio- economic survey coupled with the outcome of public consultation held. The R&R package shall be prepared after consultation with the representatives of the project affected families and the State Government. Detailed budgetary estimates are to be provided. Resettlements site should be identified. The plan will also incorporate community development strategies.
14. Special attention has to be given to vulnerable groups like women, aged persons etc. and to any ethnic/indigenous groups that are getting affected by the project.
15. Impacts of blasting activity during project construction which generally destabilize the land mass and leads to landslides, damage to properties and drying up of natural springs and cause noise population will be studies. Proper record shall be maintained of the baseline information in the post project period.
16. All muck disposal sites should be minimum 30 m away from the HFL of river. The quantity of muck to be generated and the quantity of muck proposed to be utilized

shall be calculated in consultation with the project authorities. Details of each dumping site viz. area, capacity, total quantity of muck that can be dumped etc. should be worked out and discussed in the plan. Plan for rehabilitation of muck disposal sites should also be given. The L-section / cross section of muck disposal sites and approach roads should be given. The plan shall have physical and financial details of the measures proposed. Layout map showing the dumping sites vis-à-vis other project components will be prepared and appended in the chapter.

17. A detail of the source (quantum of water available, other potential users etc.) from where water is envisaged to be lifted shall be furnished.
18. Places where diversions of nallah/natural drains are proposed should be detailed out in the EIA report.
19. Sedimentation study in the pipe lines including the deposition, scaling etc should be furnished with EIA report along with the methodology proposed for its cleaning.
20. Economic viability and cost benefit analysis be conducted and presented in the EIA report and should also take into consideration environmental/ecological factors.
21. How micro-irrigation technology shall be implemented in this project after the completion of the project should be discussed in the EIA report.
22. The study area for the EIA shall include 2.5 Km area on either sides of the pipeline.
23. Management plan for dug-out material generated during laying / construction of the pipe line / structures.
24. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
25. Muck management plan wrt mechinary deployment and movement of trucks shall be discussd in the EIA report.
26. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented and assessment of ecological services and damage with respect to flora & fauna air, water, land and other environmental attributes shall be studied and reported in EIA report.
27. PP should also explore the possibility of reducing proposed power requirement and methods proposed for dealing with back pressure in case of electricity failure should be studied in the EIA report.
28. EIA report should cover impact of anticipated change in cropping pattern and associated activities like horticulture, animal husbandry etc.
29. PP should carry out the public hearing of the site as per the procedure laid down in the EIA Notification, 2006.

16. **Case No 9745/2023 Shri Mukesh Raikwar, Executive Engineer, Narmada Development Division-23, 59, Arera Hills, NVDA, Narmada Bhawan, Bhopal (MP)-462027. Prior Environment Clearance for Handia Barrage Project in an area of 35,000 ha. CCA, GCA- 44,668 ha., Hydropower Generation-25 MW, Length of the Dam (m) -777meters, No. of Turbine Generating unit (MW) -05 nos. Total design discharge -1.75 Cumec., at Kundgaon Khurd village Dewas and Harda (MP). Category-1-c, [under River Valley and Hydroelectric Projects].**

This is a River Valley projects involving > 10,000 ha. of culturable command area falls under category "B" and have been mentioned at SN. 1(c) column B of Schedule of EIA Notification, hence such projects are required to obtain prior EC from the SEIAA.

This is case of Prior Environment Clearance for Handia Barrage Project [under River Valley and Hydroelectric Projects] in an area of 35000 ha. CCA at Kundgaon Khurd village Dewas and Harda (MP).

The case was presented by the Dr. Sandeep Jadhav, Env. Consultant from M/s. MITCON, Pune along with PP Shri Mukesh Raikwar, Executive Engineer, Narmada Development Division-23, 59, NVDA, Narmada Bhawan, Bhopal, (Online) wherein PP stated that the proposed Handia Barrage Project will be constructed on Main Narmada River at Near Village Kundgaon Khurd in Dewas District. Handia Barrage Project is planned to cater 35,000 ha CCA in 72 villages in Dewas and Harda districts, Madhya Pradesh with gross capacity of 140.93 MCM. Tehsil Handia will be at Left Bank of Project whereas on the Right Bank Tehsil Khategaon. PP submitted following salient features of the project:

Name of the Project	Handia Micro Lift Irrigation Project
Type of the Project	Irrigation & Power
Location	Near Village KUNDGAON KHURD
Latitude	22°29'47.01"N
Longitude	77°0'21.64"E
Located on River	Narmada River
Tehsil	Handia at Left Bank /Khategaon at Right Bank)
District	Harda / Dewas
Type of Dam	Concrete
Dam height from the deepest foundation level (m)	24.50
Length of the Dam (m)	777
Maximum Height of the Embankment	11
Type of Spillway	Ogee
No. of Spillways	31
Irrigation Project CCA	35000 ha

GCA (ha.)	44668 ha
Hydropower Generation	25 MW
No. of Turbine Generating unit (MW)	5
Capacity of each turbine (MW)	5
Size of the Power House Cavern (m) (L*W*H	70*15*12
Total design discharge (Cumec)	1.75
Length of Main Canal	87 km
Length of Distributary	910 km
No. of Stream crossing	4
Type of Irrigation	Flood as well as drip
Benefited Village	72 in Dewas District

Command Area Details

District	Villages Benefited	Projected GCA in Ha	Created CCA in ha.
Dewas	72	35000	44668
Total	**72**	**35000**	**44668**

Land Requirement

Nature of Land	Requirement in (Ha)
Non-Forest Land	**200**
Forest Land	**0**
Total	**200**

During presentation, PP submitted that no forest land is involved in this project. Committee after deliberations recommended to issue standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's:-

1. Detaile diagrammatic representation of command area and any of the submergence area shall be prepared and appended with EIA report.
2. Status of land as per land recored register of concerned collector.
3. CAT plan shall be prepared and the same shall be approved by the concerned DFO.
4. KML of FC clearance and EC clearance shall be submittd with EIA report with forest compartment history as per current forest plan.
5. Thematic disgram showing channel from water lifting point to the distribution area shall be submitted with EIA report.

6. Details of actual area occupied by pipes and other other area (such as for movement of trucks and logistic support) shall be calculated and discussd in the EIA report.

7. Narmada Development Division has applied for distance from nearby National Park/ WLS vide letter no. 206 dated 13.01.23 and the same shall be submitted with EIA report.

8. Narmada Development Division has applied for interstate distance of the project vides letter no. 207 dated 13.01.23 and the same shall be submitted with EIA report.

9. Tectonics, seismicity and history of past earthquakes in the area. A site specific study of the earthquake parameters will be done. The results of the site specific earthquake design shall be sent for approval of the NCSDP (National committee of Seismic Design Parameters, Central water commission, New Delhi for large dams.

10. If any issue involved to R&R, shall be elaborated in EIA with proper provisions issued by various State /central Government orders/ notification. In case of R&R is proposed then list of all the Project Affected Families (PAFs) with their name, age, educational qualification, family size, sex, religion, caste, sources of income, land & house holdings, other properties, occupation, source of income, house/land to be acquired for the project and house/land left with the family, any other property, possession of cattle, type of house etc.

11. Resettlement and Rehabilitation Plan needed to be prepared on the basis of findings of the socio- economic survey coupled with the outcome of public consultation held. The R&R package shall be prepared after consultation with the representatives of the project affected families and the State Government. Detailed budgetary estimates are to be provided. Resettlements site should be identified. The plan will also incorporate community development strategies.

12. Special attention has to be given to vulnerable groups like women, aged persons etc. and to any ethnic/indigenous groups that are getting affected by the project.

13. Impacts of blasting activity during project construction which generally destabilize the land mass and leads to landslides, damage to properties and drying up of natural springs and cause noise population will be studies. Proper record shall be maintained of the baseline information in the post project period.

14. All muck disposal sites should be minimum 30 m away from the HFL of river. The quantity of muck to be generated and the quantity of muck proposed to be utilized shall be calculated in consultation with the project authorities. Details of each dumping site viz. area, capacity, total quantity of muck that can be dumped etc. should be worked out and discussed in the plan. Plan for rehabilitation of muck disposal sites should also be given. The L-section / cross section of muck disposal sites and approach roads should be given. The plan shall have physical and financial details of the measures proposed. Layout map showing the dumping sites vis-à-vis

other project components will be prepared and appended in the chapter.

15. A detail of the source (quantum of water available, other potential users etc.) from where water is envisaged to be lifted shall be furnished.

16. Places where diversions of nallah/natural drains are proposed should be detailed out in the EIA report.

17. Sedimentation study in the pipe lines including the deposition, scaling etc should be furnished with EIA report along with the methodology proposed for its cleaning.

18. Economic viability and cost benefit analysis be conducted and presented in the EIA report and should also take into consideration environmental/ecological factors.

19. How micro-irrigation technology shall be implemented in this project after the completion of the project should be discussed in the EIA report.

20. The study area for the EIA shall include 2.5 Km area on either sides of the pipeline.

21. Management plan for dug-out material generated during laying / construction of the pipe line / structures.

22. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.

23. Muck management plan wrt mechinary deployment and movement of trucks shall be discussd in the EIA report.

24. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented and assessment of ecological services and damage with respect to flora & fauna air, water, land and other environmental attributes shall be studied and reported in EIA report.

25. PP should also explore the possibility of reducing proposed power requirement and methods proposed for dealing with back pressure in case of electricity failure should be studied in the EIA report.

26. EIA report should cover impact of anticipated change in cropping pattern and associated activities like horticulture, animal husbandry etc.

27. PP should carry out the public hearing of the site as per the procedure laid down in the EIA Notification, 2006.

17. <u>Case No 9757/2023 Shri Narayan Das Vaishya, Partner, M/s Singrauli Mineral Products Private Limited, R/o Village-Gadsa, Post-Pondi Naugai, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP)-486886 Prior Environment Clearance for Phulwari Stone Quarry in an area of 3.00 ha. (45230 Cum per annum) (Khasra No. 290, 291 Govt.), Village-Phulwari, Tehsil-Singrauli, District- Singrauli (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 290, 291 Govt.), Village-Phulwari, Tehsil-

Singrauli, District- Singrauli (MP) 3.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री नारायण दास बैश्य (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराधव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजराज) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 565 दिनांक 14/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर–पूर्व दिशा में लगभग 50 मीटर की दूरी पर, दक्षिण–पूर्व दिशा में 33 मी. पर एंव उत्तर–पूर्व दिशा 100 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड है तथा पश्चिम दिशा में 100 मीटर पर 1–2 मकान दिख रहे है। अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 565 दिनांक 14/02/2023 अनुसार सूचित किया गया है कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन के पूर्व यह उत्खनन पट्टा स्वीकृत नही था तद्नुसार आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे इसे शामिल कर लिया जावेगा। **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है।** उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के उत्तर–पूर्व दिशा में लगभग 50 मीटर की दूरी पर, दक्षिण–पूर्व दिशा में 33 मी. पर एंव उत्तर–पूर्व दिशा 100 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड है तथा पश्चिम दिशा में 100 मीटर पर 1–2 मकान दिख रहे है। अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

6. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 565 दिनांक 14/02/2023 अनुसार सूचित किया गया है कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन के पूर्व यह उत्खनन पट्टा स्वीकृत नही था तद्नुसार आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे इसे शामिल कर लिया जावेगा। आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जायेगा अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये।
8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

18. <u>Case No 9764/2023 Shri Aruna Sihare, Proprietor, R/o Civil Lines, Tilak Ward, District-Mandla (MP)-481661, Prior Environment Clearance for Bhanwartal Dolomite Mine in an area of 6.60 ha. (70050 Ton per annum) (Khasra No. 110, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 20/5 Govt. and Pvt.) Village- Bhanwartal, Tehsil-Bhichhiya, District-Mandla (MP)</u>

This is case of Dolomite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 110, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 20/5 Govt. and Pvt.) Village- Bhanwartal, Tehsil-Bhichhiya, District-Mandla (MP) 6.60 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अरूण सिहारे (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रेएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1712 दिनांक 13/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 15.29 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार लीज क्षेत्र के अंदर उत्तर पूर्व से दक्षिण–पूर्व दिशा में ग्रीन बेल्ट पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रकरण क्षमता विस्तार का है किंतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति एवं बोर्ड की सम्मति ऑनलाईन अपलोड नहीं की गई है, अतः परियोजना प्रस्तावक पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति एवं बोर्ड की सम्मति ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे। इसी प्रकार प्रकरण क्षमता विस्तार है, पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का पालन प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवेदित क्षेत्र के खसरा नं. 113 एवं 114 उत्तरी एवं पूर्वी सीमा वन सीमा से लगी हुई है तथा कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर की बैठक दिनांक 02/11/22 में स्वीकृत क्षेत्र का वन विभाग विभाग की उपस्थिति में संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर वन कक्ष क्रमांक 757, 755 (वन सीमा) की ओर आवेदित वन क्षेत्र में 6 से 10 गेज की 4 व्यास की जाली से चेनलिंग–फेंसिंग (बिना बारवेट) करने

तथा वन सीमा की ओर आवेदित क्षेत्र में स्वयं के व्यय पर वृक्षारोपण तथा वृक्षारोपण का खदान अवधि तक संरक्षण करने की शर्त पर अनापत्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–27 के सरल क्रमांक–4 पर दर्ज है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:–

1. लीज क्षेत्र के अंदर उत्तर पूर्व से दक्षिण–पूर्व दिशा में ग्रीन बेल्ट पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये साथ ही इकोलॉजिकल सर्विसेस एवं डेमेज एसेसमेंट रिपोर्ट भी ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. प्रकरण क्षमता विस्तार का है किंतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति एवं बोर्ड की सम्मति ऑनलाईन अपलोड नहीं की गई है, अतः परियोजना प्रस्तावक पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति एवं बोर्ड की सम्मति ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे।
3. इसी प्रकार प्रकरण क्षमता विस्तार है, पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का पालन प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

19. <u>Case No 9769/2023 Shri Mool Maravi, Executive Engineer, Narmada Development Division No. 2, Civil Line, Near SBI Bank, District-Mandla (MP)-481661. Prior Environment Clearance for Raghavpur Multi-Purpose Project and 25 MW Powerhouse in an area of over CCA of 17587 ha. Gross command area -25124 ha, Irrigable command area-17587 ha, Dam length- 580.00 m dam maximum height of 61.00 m, Gross storage 645.20 MCM, Live storage of 489.96 MCM at Village-Marwari, Tehsil-Shahpura, District-Dindori (MP). [under River Valley and Hydroelectric Projects]</u>

This is a River Valley projects involving > 10,000 ha. of culturable command area falls under category "B" and have been mentioned at SN. 1(c) column B of Schedule of EIA Notification, hence such projects are required to obtain prior EC from the SEIAA.
This is case of Prior Environment Clearance for Raghavpur Multi-Purpose Project and 25 MW Powerhouse [under River Valley and Hydroelectric Projects] in an area of over CCA of 17587 ha. at Village-Marwari, Tehsil-Shahpura, District-Dindori (MP).

The case was presented by the Mr. Ravinder Bhatia, Env. Consultant from M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon (Haryana) along with PP Shri Mool Maravi, Executive Engineer, Narmada Development Division District-Mandla with the following details of the project:

Summary of the Project:

The Raghavpur Multipurpose Project is located near Marwari village of Shahpura Tehsil in Dindori District of Madhya Pradesh having latitude 23°00`59``N and longitude 80°53`03``E. The site can be located on toposheet no 64A/16, 64B/13, 64F/1 and 64E/4. The site is situated about 50 km away from Dindori and 108 km away from Mandla District H.Q.

The project is planned by NVDA as part of Bargi system along with other projects to store and distribute Narmada water for drinking and irrigation out of Madhya Pradesh share of water as per NWDT award. The Narmada River basin drains out very fast which causes scarcity of surface and ground water in surrounding areas. No further development in the agriculture, industrial, and other activities is possible without enriching the region with water. By creating major storages, development of presently backward area is possible. There is sufficient culturable land hence this scheme is necessary to provide irrigation in remote and backward area as well as to resolve flood control problem in the downstream areas.

Bargi System will face a shortage of the order of 900MCM, which in turns demands creation of additional storage of at least 600MCM with reservoir operational factor of 1.5 to effectively remove the water deficit of 900 MCM of the Bargi Reservoir. Integrating Bargi reservoir with Raghavpur, and Basania (another planned project of NVDA on Narmada) is considered extremely important to have adequate storage capacity.

The project comprises of four main components namely Head Works (earthen dam with Central Spillway and Appurtenant works), Pump House, Distribution Chamber, Pressurized Canal works and Power House. The important project components are:

- 580.00 m long Dam with a maximum height of 61.00 m.
- 171.00 m long Central Spillway & 224.00 m NOF including key wall (on both side) with 9 gates (15mx17m each)
- 185.00 m long earthen section on either side of the Dam portion
- Storage capacity - gross storage 645.20 MCM, live storage of 489.96 MCM

Pressurized pipe system of approx. 62.60 Km long with micro network system to irrigate 17587 ha. area of Dindori district is part of the project. Submergence area at FRL of 665m is 4600 ha. Breakup of land under submergence is as under:

1. No. of villages partially submerged : 48 no.
2. Total submergence area in hectare : 4600 ha
   (a) Private Land : 2636 ha (Irrigated-1054 ha, Unirrigated- 1582 ha)
   (b) Government/Revenue land : 1952 ha
   (c) Forest land : 12.00 ha
3. Submergence of private land will affect about 957 families, who will be compensated as per the law.

   Command Area details are as follows:

1. Gross command area : 25124 ha
2. Irrigable command area : 17587 ha
3. Proposed Rabi area : 17587 ha
4. Proposed Kharif area : 0 ha
5. Annual Irrigation : 17587 ha.

Salient features of Raghavpur Multipurpose Project are as under:

LOCATION		
1	State	Madhya Pradesh
2	District	Dindori
3	Tehsil/Block	Shahpura
4	Toposheet No	64A/16,64B/13,64F/1,64 E/4
5	Latitude	23°00`59``N
6	Longitude	80°53`03``E
7	River	Narmada
8	River Sub Basin	Narmada

9	River Basin	Narmada
10	Tribal/ Non-Tribal	Tribal
11	Distance	50 Km from Dindori and 108 Km from Mandla
13	Irrigation proposed	17587 Ha
HYDROLOGY		
1	Catchment Area	3228 Sq. Km
2	Maximum Flood Discharge (PMF)	23656 Cumec
3	Available runoff at Raghavpur	
	(i) 50% Dependable Yield	1743.12 MCM
	(ii) 75% Dependable Yield	1297.66 MCM
	(iii) 90% Dependable Yield	965.17 MCM
RESERVOIR DATA		
1	Gross Storage	645.20 MCM
2	Live Storage	489.96 MCM
3	Dead Storage	155.24 MCM
4	Gross Area of Submergence at F.R.L	4600 Ha
5	Private Land	2636 Ha
6	Government Land	1952 Ha
7	Forest Land	12.00 Ha
8	Details of Villages Submerged	
	No. of Villages Fully Submerged	Nil
	No. of Villages Partially Submerged	48 Nos of Villages (1. Khurpar ryt, 2. Junwani mal, 3. Padariya ryt, 4. Raipura mal, 5. Marwahi ryt, 6. Kalagitola mal, 7. Kalagitola ryt, 8. Sakka mal, 9. Mudhiya mal, 10. Khairda ryt, 11. Barga ryt, 12. Sakka ryt, 13. Kisalpuri mal, 14. Chhapari mal, 15. Chhapari ryt, 16. Rampuri mal, 17. Dindori (Np), 18. Soobkhar mal, 19. Imlai mal, 20. Imlai ryt, 21. Rahangi mal, 22. Deora mal, 23.Vicharpur ryt, 24. Chaura mal, 25. Chaura ryt, 26. Chhindgaon mal, 27. Chhindgaon ryt, 28. Kurkwara mal, 29. Kurkwara ryt, 30. Mudhiya Kalan mal, 31. Mudiya khurd, 32. Saliwada mal, 33. Saliwada ryt,34. Gangpur mal, 35. Soobkhar ryt, 36. Ghusiya ryt, 37. Aurai mal, 38. Dhaurai mal, 39. Dhaurai ryt, 40. Fadki mal ,41. Khamee ryt, 42. Vidyapur ryt, 43. Khamee mal, 44. Vikrampur ryt, 45. Jogitikariya, 46.Hinauta mal, 47. Kevlari mal, 48.Kevlari ryt (may change after the Detailed survey)
9	Family Affected	Approx. 957 families
10	Nos of Benefitted Villages	52 Nos
DAM DATA		
1	Type of Dam	Composite Dam
2	Total Length including earthen bund	580.00 M
3	Length of Spillway	171.00 M
4	Height	61.00 M

5	No. of Openings/Gates	9 Nos
6	Size of Gates	15 M (Width) X 17 M (Height)
7	Crest Level	648.00 M
8	Thickness of Pier	4.50 M
9	Free board above M.W.L.	2.50 M
CONTROL LEVEL		
1	T.B.L.	669.00 M
2	M.W.L.	666.50 M
3	F.R.L.	665.00 M
4	M.D.D.L.	648.00 M
	CANAL	
1	Length of Rising Main and gravity Main	62.60 KM (Approx)
2	Max. dia of Rising Main or Gravity Main	1.19 M
3	Power Required	7.85 MW
AREA PROPOSED UNDER IRRIGATION		
1	Gross Command Area	25124 Ha
2	Cultural Command Area	17587 Ha
3	Crop Kharif	Nil
4	Crop Rabi	17587 Ha
5	Crop perennial	Nil
	Total	**17587 Ha**
POWER		
1	Power Generation	(12.5x2=25) MW
COST BENEFIT RATIO		
1	Cost Benefit Ratio	1.51

During presentation committee suggested that in the project area there is possibility of getting fossils and if such situation arises the recovered fossils shall be deposited with concerned DFO. Committee after deliberations recommended to issue standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's:-

1. Since project involves 12.00ha. Forest area, F.C. clearance has to be obtained by PP and copy of the same should be submitted with EIA report.
2. Detaile diagrammatic representation of command area and any of the submergence area shall be prepared and appended with EIA report.
3. Status of land as per land recored register of concerned collector.
4. CAT plan shall be prepared and the same shall be approved by the concerned DFO.
5. KML of FC clearance and EC clearance shall be submittd with EIA report with forest compartment history as per current forest plan.

6. Thematic disgram showing channel from water lifting point to the distribution area shall be submitted with EIA report.
7. Details of actual area occupied by pipes and other other area (such as for movement of trucks and logistic support) shall be calculated and discussd in the EIA report.
8. In the project area there is possibility of getting fossils and if such situation arises the recovered fossils shall be deposited with concerned DFO.
9. It shall also be verified if any area is falling under PESA Act, 1996, if yes their provisions shall accordingly be complied.
10. Tectonics, seismicity and history of past earthquakes in the area. A site specific study of the earthquake parameters will be done. The results of the site specific earthquake design shall be sent for approval of the NCSDP (National committee of Seismic Design Parameters, Central water commission, New Delhi for large dams.
11. If any issue involved to R&R, shall be elaborated in EIA with proper provisions issued by various State /central Government orders/ notification. In case of R&R is proposed then list of all the Project Affected Families (PAFs) with their name, age, educational qualification, family size, sex, religion, caste, sources of income, land & house holdings, other properties, occupation, source of income, house/land to be acquired for the project and house/land left with the family, any other property, possession of cattle, type of house etc.
12. Resettlement and Rehabilitation Plan needed to be prepared on the basis of findings of the socio- economic survey coupled with the outcome of public consultation held. The R&R package shall be prepared after consultation with the representatives of the project affected families and the State Government. Detailed budgetary estimates are to be provided. Resettlements site should be identified. The plan will also incorporate community development strategies.
13. Special attention has to be given to vulnerable groups like women, aged persons etc. and to any ethnic/indigenous groups that are getting affected by the project.
14. Impacts of blasting activity during project construction which generally destabilize the land mass and leads to landslides, damage to properties and drying up of natural springs and cause noise population will be studies. Proper record shall be maintained of the baseline information in the post project period.
15. All muck disposal sites should be minimum 30 m away from the HFL of river. The quantity of muck to be generated and the quantity of muck proposed to be utilized shall be calculated in consultation with the project authorities. Details of each dumping site viz. area, capacity, total quantity of muck that can be dumped etc. should be worked out and discussed in the plan. Plan for rehabilitation of muck disposal sites should also be given. The L-section / cross section of muck disposal sites and approach roads should be given. The plan shall have physical and financial

details of the measures proposed. Layout map showing the dumping sites vis-à-vis other project components will be prepared and appended in the chapter.

16. A detail of the source (quantum of water available, other potential users etc.) from where water is envisaged to be lifted shall be furnished.
17. Places where diversions of nallah/natural drains are proposed should be detailed out in the EIA report.
18. Sedimentation study in the pipe lines including the deposition, scaling etc should be furnished with EIA report along with the methodology proposed for its cleaning.
19. Economic viability and cost benefit analysis be conducted and presented in the EIA report and should also take into consideration environmental/ecological factors.
20. How micro-irrigation technology shall be implemented in this project after the completion of the project should be discussed in the EIA report.
21. The study area for the EIA shall include 2.5 Km area on either sides of the pipeline.
22. Management plan for dug-out material generated during laying / construction of the pipe line / structures.
23. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
24. Muck management plan wrt mechinary deployment and movement of trucks shall be discussd in the EIA report.
25. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented and assessment of ecological services and damage with respect to flora & fauna air, water, land and other environmental attributes shall be studied and reported in EIA report.
26. PP should also explore the possibility of reducing proposed power requirement and methods proposed for dealing with back pressure in case of electricity failure should be studied in the EIA report.
27. EIA report should cover impact of anticipated change in cropping pattern and associated activities like horticulture, animal husbandry etc.
28. PP should carry out the public hearing of the site as per the procedure laid down in the EIA Notification, 2006.

20. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा

अ. मुरैना– रेत खनिज

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र0. 331 दिनांक 20/03/2023 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, मुरैना (रेत खनिज) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिति का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है ।

आज दिनांक 21/03/23 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई । चर्चा उपरांत पाया गया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला–मुरैना के पत्र क्र0 331 दिनांक 20/03/2023 के माध्यम से प्राप्त जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका क्र0. –06 पेज न0. 20 में माइनेबल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60ः टोटल मिनरल पोटेंशियल, लीजवार, लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ दर्शाया है ।

समिति की यह अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये ।

अतः समिति की यह भी अनुशंसा है कि मुरैना – रेत खनिज जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

ब. श्योपुर (रेत खनिज)

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र0. 2338 दिनांक 21/03/2023 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, मुरैना (रेत खनिज) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

आज दिनांक 21/03/23 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई । चर्चा उपरांत पाया गया कि खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला–श्योपुर के पत्र क्र0 2338 दिनांक 21/03/2023 के माध्यम से प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के बिंदु क्रमांक–14 की तालिका–6 पेज नं. 18 पर माइनेबल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60ः टोटल मिनरल पोटेंशियल, लीजवार, लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ दर्शाया है ।

समिति की यह अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये ।

अतः समिति की यह भी अनुशंसा है कि श्योपुर रेत खनिज जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

स. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पन्ना – अन्य गौण खनिज –संशोधित

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र0. 364 दिनांक 21/03/2023 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, मुरैना (रेत खनिज) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

632वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मार्च 2023

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 632 वीं बैठक दिनांक 21/03/22 में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) (संशोधित) पर चर्चा की गई चर्चा के दौरान खनिज विभाग की ओर से श्री रवि कुमार पटेल, खनिज अधिकारी उपस्थित हुये । चर्चा के दौरान समिति ने खनिज अधिकारी को बताया कि सेक की पूर्व बैठकों में दिए गए सुझावों के अनुसार अन्य गौण खनिज की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पुनरीक्षित कर ली गई है ।

जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अवलोकन करने पर समिति ने पाया कि समिति के पूर्व बैठकों में दिए गए सुझावों / अधिसूचना के अनुरूप रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक–निरंक (पेज न0. 35–85) में खदान की जानकारियों का विवरण दर्ज किए गए है । साथ ही जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी टेबिल क्रमांक–निरंक (पेज क्र0. 116–129) मे दे दी गई है।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला– पन्ना के पत्र क्र0 364 दिनांक 2109/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है । अतः समिति मुरैना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.

20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/

Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'
Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest

shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.

18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'
Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain

a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.
    q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.

15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.

33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

- ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
- ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
- ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :

- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
- ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पैधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास प्रजातियॉ ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, कंरज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास अगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

632वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 मार्च 2023